संपादकीय

बी.एस.एन.एल में मानव संसाधन विकास

किसी भी उद्योग में उसके समुचित संचालन एवं विकास के लिए मानव संसाधन एक मुख्य कारक समझा जाता है। उद्योग चाहे सेवा प्रदान करती हो या उत्पादन करने की इकाई हो, मानव संसाधन को प्रमुख भूमिका मानी गयी है। इसलिए मानव संसाधन अर्थात कर्मचारियों को विकसित करने की व्यवस्था मनाई जाती है। हमारा बी.एस.एन.एल एक सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है और यह कंपनी सम्पूर्ण राष्ट्रीय पैमाने पर दूरसंचार सेवाएं प्रदत्त करती है।

पूर्व में दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के अधिनस्त इस सेवा का संचालन किया जाता था और मानव संसाधन को विशेष प्राथमिकता दी जाती थी परंतु जब दूरसंचार परिचालन एवं दूरसंचार सेवा विभाग को निगम में परिवर्तित किया गया तो 1.10.2000 से भारत संचार निगम का प्रादुर्भाव हुअर। प्रारम्भ में पूर्व की भांति मानव संसाधन को विकसित करते रहने की प्रक्रिया जारी रही परंतु जब सरकार को नीतियों एवं प्रबंधन की अदूरदर्शिता के कारण जब कंपनी में आर्थिक गिरावट आने लगी तो मानव संसाधन यानी कर्मचारियों को समस्या माना जाने लगा। मानव संसाधन के विकास से तात्पर्य है, आवश्यकता जनित कर्मियों की भर्ती करना, उन्हें प्रक्षिशित करना, उनके कार्य स्थल पर कार्य करने की स्थिति प्रदान करने, उनके चिकित्सा का प्रबंधन करना, पदोन्नति की परीक्षाएं आयोजित करना, कल्याण जनित व्यवस्थाए विकसित करना, खेलकूद की व्यवस्था आदि के द्वारा एक विकसित कार्य बल तैयार करने को ही मानव संसाधन विकास के दायरे में समझा जाता है। डी.ओ.टी.के समय सारी व्यवस्थाएं समुचित ढंग से चलायी जाती थी।

निगम बनने के बाद इसके समुचित संचालन के लिए एक बोर्ड की गठन की गई जिसमें अध्यक्षता एवं प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त पांच अन्य निदेशकों में निदेशक मानव संसाधन एवं विकास का पद भी बनाया गया। वर्ष 2017 तक नियुक्तियां होती रही, प्रशिक्षण होते रहे, कल्याणकारी योजनाएं चलती रही, पदोन्नति की परीक्षाएं होती रही, समयबद्ध पदोन्नति भी दी जाती रही परंतु उसके बाद कंपनी की आर्थिक गिरावट के लिए प्रबधन अपनी विफलता का ठीकरा कर्मचारियों के सर पर फोड़ने लगी। यह कहा जाने लगा कि कंपनी के राजस्व प्राप्ति का पचास प्रतिशत से ज्यादा भाग कर्मचारियों पर खर्च हो जाता है।

इस परिपेक्ष में दूरसंचार विभाग सलाहकार नियुक्त करनी शुरु की ओर उनसे बी.एस.एन.एल के पुनरुथान के लिए अनुसंशाएं मांगी जाने लगी। डी.ओ.टी. एवं बी.एस.एन.एल बोर्ड के कार्यरत सभी उच्च पदस्थ अधिकारियों की नाकामी को नजर अंदाज किया गया और बाहरी प्रतिष्ठानों को बी.एस.एन.एल की भाग्य बदलने के लिए कुण्डली बनाने की जिम्मेवारी दी जाने लगी। उनके अनुशंसाओं के अनुरुप कार्य शुरु हुए। अततः आई.आई.एन अहमदाबाद को भी सलाहकार नियुक्त किया गया, जिसने अनुसंचित किया कि कर्मचारियों की भारी संख्या को घटाकर तीस हजार कर दिये जाए, तथा अन्य कई टिप्पणियों के साथ इस संस्थान ने कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण करने की भी अनुशंसा भी कि जिससे कर्मचारियों को उत्साहित किया जा सके।

इन समस्त अनुशंसाओं को किनारे रखते हुए सरकार एवं प्रबंधन ने कर्मचारी विरोधी कार्यवाईयों पर ध्यान केन्द्रित किया तथा भारत सरकार की मंत्री परिषद ने 21 अक्टूबर 2019 को बी.एस.एन.एल के लिए पुनरुत्थान पैकेज को अनुमोदित किया। इस पैकेज में आठ बिन्दुएं थी परंतु सबको किनारे करते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वी.आर.एस) द्वारा कर्मचारियों को बाहर करने की अनुशंसा को प्राथमिकता देते हुए 31 जनवरी 2020 को 78648 कार्यपालक एवं अकार्यपालक कर्मचारियों को सेवा से बाहर कर दिया गया। आधे से अधिक कर्मचारियों को सेवा से बाहर चले जाने के उपरांत कंपनी की राजस्व में भारी गिरावट हुई और राजस्व उगाही पचास प्रतिशत नीचे आ गई यहां यह स्पष्ट हो गया कि कर्मचारी किसी भी विकास के लिए आवश्यक तत्व है। इस वी.आर.एस के बाद कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना बंद हो गया, पदोन्नति संबधी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। चिकित्सा भत्तो का भुगतान बंद हो गया। कर्मचारियों के चेहरे से मुस्कुराहट छीन गई। कैडर पुनर्गठन के नाम पर वी.आर.एस के पूर्व सम्पूर्ण रिक्त पदों को समाप्त कर दिया गया।

समय पर वेतन के लिए कर्मचारी लगातार संघर्षरत रहे। कर्मचारियों के एकजुट संघर्ष के बाद जनवरी 2022 से समय पर वेतन भुगतान संभव हो सका है।

जहां तक मानव संसाधन को विकसित करने का सवाल है, वर्तमान में इस महत्वपूर्ण कारक को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। कर्मचारियों के अधिकारों को निर्दयतापूर्वक समाप्त कर दिया गया है।

वेतन पुनरीक्षण कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण 01.01.2017 से लम्बित है। कंपनी को घाटे में होने का बहाना बनाकर सरकार ने कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण नही किया। छः वर्ष बीत जाने के बावजूद इस दिशा में कोई प्रगति नहीं है। डी.ओ.टी से स्थानान्तरित होकर बी.एस.एन.एल में सम्मिलित कर्मचारियों की कुल संख्या के 60 प्रतिशत कमचारियों वेतन अवनद्धम का शिकार हो चुके हैं, और यह

पीड़ादायक विकृत स्थिति दिनानुदिन बढ़ते जा रही है। कर्मचारी बिना किसी वार्षिक वेतन बढ़ोतरी के साल–दर साल कार्य करते रहने को बाध्य किये जा रहे है।

मानव संसाधन की विकृत स्थिति यहां तक पहुच गई है कि कंपनी में कार्यरत 3500 टेम्पोरेरी स्टैटस मजदूर एवं आकस्मिक मजदूर 01.01.2010 का निर्धारित मजदूरी पर कार्य कर रहे है। नियमतः इनकी मजदूरी सातवें वेतन आयोग के सिफारिसों के आधार पर 01.01.2020 से इन कर्मचारियों को मजदूरी तय होनी चाहिए थी परंतु राजस्व में कमी का रोना रोते हुए बी.एस.एन.एल प्रबंधन इन अति अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को भी पीड़ित कर रही है। इसी प्रकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन पुनरीक्षण 01.01.2017 से हो जाना चाहिए था, परंतु इस भी अनसूनी करते हुए सरकार ने उन्हें कोर्ट की शरण लेने को बाध्य कर दिया। पेंशनरों के संगठनों ने प्रिंसिपल बैंच कैंट नई दिल्ली में याचिका दायर की ओर कोर्ट के स्पष्ट निर्णय के बावजूद सरकार पेंशनभोगी वरिष्ठ नागरिकों को सड़को पर उतरने को बाध्य करते रही है।

जहां तक कर्मचारियों की चिकित्सा का सवाल है, वह भी नगण्य हो चुकी है अति प्रसंनीय बी.एस.एन.एल.आर.एस की सुविधा ध्वस्त हो चुकी है। कैशलेश इलाज पूरे भारत में बंद कर दी गई है, परंतु कार्पोरेट कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों के लिए दिल्ली के अस्पतालों में कैशलेश चिकित्सा की सुविधा जारी है, जो अत्यंत भेदभावपूर्ण है। कर्मचारी अपने वेतन से पैसे खर्च करके स्वास्थ्य बीमा के तहत बीमा कराने को बाध्य हो रहे है।

कर्मचारियों के सुरक्षा कवच के रुप में पूर्व में प्रदत अनुकम्पा अधारित नियुक्ति को सन 2019 में तीन वर्ष के लिए रोक लगाई गई की, जिसकी सीमा मार्च 2022 में समाप्त होने की थी, परंतु फरवरी 2022 से इसे अनिश्चितकाल के लिए पाबन्दित कर दिया गया है।

कर्मचारियों के पदोन्नति के समस्त रास्ते बद कर दिये गये है। नान–एक्जीक्यूटिव प्रमोशन पालिसी का महत्व समाप्त हो चुका है। सभी मान्यता प्रच्त संगठन नयी पदोन्नति नीति बनाने की मांग करते रहे है। परंतु प्रबंधन इसे मानने को कभी तैयार नहीं होती है।

विभागीय पदोन्नति की परीक्षाओं की स्थिति और भी भयावह है। रिक्तियों के अभाव में आधे सकिंलों में किसी भी संवर्ग के लिए परीक्षाएं आयोजित नहीं हो रही है, जिसने कर्मचारियों का भविष्य अनिश्चय की स्थिति में है।

सभी नवागन्तुक, शिक्षित, उर्जावान, जे.ई तथा दूसरे कर्मचारी जां बी.एस.एन.एल में सीधी भती से आये है, उनकी स्थिति और भयावह होते जा रही है। इनके पदोन्नति की स्थिति नगण्य बनी हुई है, साथ ही द्वितीय वेतन पुनरीक्षण की डी.पी.ई की सिफारिसों के अनुरुप इनके सामाजिक सुरक्षा एवं सेवानिवृत्ति लाभ के लिए 30% की निर्धारित राशि प्रत्येक सीधी भर्ती वाले श्रम कर्मचारियों के लिए जमा नहीं कराई जा रही है।

मानव संसाधन की स्थिति पर अधोपरान्त अवलोकन के उपरांत यह प्रतीत हो रहा है कि सरकार एवं बी.एस.एन.एल प्रबंधन कंपनी को रवानगी ठेकेदारों एवं बाध्य एजेन्सी के द्वारा ही चलाना चाहती है। कर्मचारियों को मीठा जहर पिलाकर कार्य से वंचित रखा जा रहा है।

मानव संसाधन के विकास की भयावकता यहां तक पहुंच गई है कि मुंबई के सभी प्रमुख स्थानों पर स्थिति बी.एस.एन.एल के आवास में रहने वाले कर्मचारियों को आवास खाली करने को नोटिस दी जा रही है, इसी प्रकार की स्थित लखनऊ में भी उत्पन्न हुई है। पूर्ण रुप से आवंटित आवास वाले कालोनियों को मोनेटाइजेशन के लिए खाली कराने हेतु प्रबंधन तैयार है। जब कि मोनेटाइजेशन के लिए ऐसा निर्धारित किया गया था कि जो बी.एस.एन.एल के जमीन बिना इस्तेमाल के खाली पड़े है, उन्हे मोनेटाइज किया जा सकता है। अभी पिछले पखवाड़े में एक अघातपूर्ण खबर आई है डी.ओ.टी ने एक राष्ट्रपतीय आदेश के द्वारा 81 एकड़ में फैले गाजियाबाद स्थित ए.एल.टी.टी.सी को बी.एस.एन.एल से ले लेने के निर्णय किये है यहा निगम बनने के समय सरकार एवं संगठनों के बीच हुये समझौते के बिल्कुल प्रतिकुल है। निगम बनते समय यह लिखित निर्णय निर्गत किया गया था कि निगम के प्रभाव में आने के दिन से ही बी.एस.एन.एल को स्थानांतरित कर दिये जायेंगे। सरकार अपने लिखित वादों से मुकरती जा रही है और यह स्थिति अति सोचनीय है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब बी.एस.एन.एल के जीवंतता पर भी प्रश्न चिन्ह है।

ऐसे में हम सभी संगठनों का एक साथ मिलकर कर्मचारियों की पूर्ण एकता एवं गोलबंदी तैयार करनी होगी तथा एकजूट होकर इस विपरीत परिस्थिति से निजात पाने का रास्ता निकालना पड़ेगा।

हम सभी जानते है कि श्रमिक संगठनों ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए अपने कामगारों को सुरक्षित रखते हुए उनके कल्याण को लगातार विकसित करते रही है। अतः इतिहास के गौरवशाली कृत्यों से सबक लेते हुए हम भविष्य की सुरक्षात्मक उपाय की संरचना कर सकते है। आइये हम सभी इस भयानक स्थिति से उबरने का संकल्प लें।

एन.एफ.टी.ई जिन्दाबाद कर्मचारी एकता जिन्दाबाद

EDITORIAL

Human resources development in BSNL

Human resources is one of the important element for better growth and smooth functioning for any industry, whether it's may be a service provider or production unit. Our BSNL is a service provider company, it provides Telecom services to the public throughout the country. Earlier in the period of DOT this element that is human resources development was being given top priority and need based recruitments were done continuously to manage the business of the department in excellent manner. After corporatization of the DTO and DTS, the Bharat Sanchar Nigam Limited came in existanance w.e.f. 01-10-2000. To manage all the affairs and business of the company, a board was constituted in which the post of Director (HR) was also created and full power was delegated to him to decide the issues of human resources development viz. recruitment, promotion, training, welfare etc. for the employees working in the company. At beginning the HR cell of Corporate office was working for all the affairs related to employees in a better manner, but later the Govt. started dilution in the issues of human resources. When the company started declining and earning of revenues were reducing, the high ranking management did not and the top level officers of DOT failed to implement such a policy which may help the company to grow. They choosed an easy path to appoint consultant and act according to reports submitted by them, one after one consultant was appointed and thus recommendations were implemented partially at the last consultant was from the Indians institute of management (IIM) Ahmadabad, which recommended to reduce the staff strength and bring down it at total thirty thousands including both executives and non-executives. The IIM Ahemdabad also recommended several points including wage revision of staff before their downsizing, but the deduction of staff strength was taken on priority basis and a revival package was announced by the union Govt. based on approved of union Cabinet on 19-10-2019. The concept of VRS was the outcome of this revival package and to make the plan success the salary payment of staff was started delayed and a kind of havoc was created in the company. The Directors were deputed in circles to ensure maximum VRS. The news was spreaded throughout the BSNL company that the remaining staff after VRS will be sent to remote and difficult areas to maintain the services of BSNL. Thus about more than 50% of workforce were sent out from BSNL through the VRS. This was the first attack of the Govt. on Job security of the staff which was a prime commitment of the Govt. at the time of Corporatisation of DTO and DTS. After VRS the earning of the company was reduced drastically and it became about fifty percent down in comparison of the revenue earned before VRS. The uncertainty on payment of salary to the staff was continued upto December 2021. Regular payment of salary started only from January 2022 and that too after a united struggle by all the Unions and Associations of BSNL. So far development of human resources is concern at present time it is in frozen stage. As neither the 3rd wage revision is implemented nor any other HR issues are taken into the consideration of the management. The employees are suffering and now the water is passing over head. All the welfare measures have been stopped one by one. **Even the wages of 3500 TSMs/Casual majdoors have not been revised from last thirteen years. Pension revision has also not been done even after a clear order from Principal Bench of CAT New Delhi. More than 60% of non-executive employees are under attack of stagnation,** the BSNL MRS has been almost collapsed, employees are taking the health insurance scheme on their individual deposit. Ban imposed on compassionate appointment for indefinite period. Promotional avenues are also in dark. **The NEPP has lost its reliability but the management is not ready to feel the need of a new promotion policy. In the same company the executives are getting for promotions in the service time bound for 5 years for one promotion.** A good number of employees of JE

Cadre are getting less salary due to non display of the scales based on 78.2% IDA merger w.e.f. 01-01-2007. Promotional examinations/LICEs are conducted in half or less of the half circles for which the employees are restless. **The junior engineers and other direct recruits of BSNL are struggling for their social security, like retirement benefits along-with pension.** The management is not implementing the recommendation of 2nd wage revision/ PRC to provide 30% SAB deposit for all direct recruits. Ban on compassionate appointments was imposed by the management from 2019 for three years. Which was to be completed in March 2022, but before completion of three years the management extended the ban on CGA indefinite period. **Thus a privilege to protect the lively hood of deceased families has been snatched by the BSNL management.** A serviceman prefers Govt. service of better pay, pension and compassionate appointments but now all these facilities provided earlier have been stopped.

Viewing all the situation it is crystal clear that the HR issues have been ignored totally and in other word the right of the workers have been brutally damaged by the management of BSNL/ Govt. All together the situation is horrible and the future of the younger, well educated, energetic, employees are in dark.

The non-executives union either jointly or on their individual capacity regularly raising the burning HR issues to the management but every efforts are going in vain.

At one hand HR issues are ignored and other hand the employees are getting notices to vacate the quarters at Mumbai and Lucknow. The fully packed colonies are listed for monetization. The staff are the stake holders of the company and they are being compelled to vacate the quarter to sell it to corporates, this type of action of the BSNL management is against the norms and natural justice. It was decided to monetize the unused land parcel and not the quarters situated at prime locations of the cities. **Just a breaking news has come that the DOT through a Presidential order is going to capture the ALTTC Ghaziabad which is located in 81 acres of land with a cost of Rs. 6000/- crores.**

All together it seems that the existence of the BSNL is in question and in this situation, we once again urge upon all to be unite and raise and we should raise a new demand that when the Govt being fully owner of the company can capture any property of company through a Presidential order, the employees of BSNL also be taken back under central Govt. through Presidential order by DOT.

The NFTE BSNL is always ready to coordinate and cooprerate with all the unions and associations of BSNL to fight against the disruption of BSNL as well as protection of employees.

NFTE Zindabad, Workers unity Zindabad